local police) as also measures to prevent the same are being constantly monitored by the Deputy Inspector General of Police, P.C.R. every month during the crime meeting and suitable instructions for effective enforcement of P.C.R. Act and Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act are being issued from time to time.

(v) The crime review is done monthly by the Deputy Superintendent of Police, Protection of Civil Rights. Supervisory Squads have been properly formated to improve their effective supervision.

(vi) Investigation and prosecution of heinous offences (Murder Rape, Arson and Grievous Hurt) registered with local police are constantly reviewed and monitored.

(vii) A well formatted memo with specific queries and directions has been designed to activate the District Superintendents of Police and their subordinates for ensuring prompt and proper police and court disposal of atrocity cases.

(viii) Intelligence collection work has been improved through well designed documents. Likewise surveys are conducted and recorded in a professional manner and the output of the intelligence collected and surveys conducted is put to effective and innovative use.

(ix) Atrocity prone areas are scientifically identified and annually updated. Improved professional policing is assured in such areas to prevent occurrence and recurrence of atrocity cases.

(x) Monetary relief is given to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes victims and/or their dependents.

(c) The details about the number of persons arrested and prosecuted pertaining to atrocity cases committed on Scheduled Castes are as under:—

	1996	1997
		(Upto 30-6-97)
(i) Number of persons arrested . . .	840	621
(ii) Number of persons prosecuted . .	320	121
(iii) Number of persons convicted . .	14	..

Regarding the number of atrocities committed on Backward Classes, State Government of Tamil Nadu was requested to send the information which is stil awaited. As soon as it is received, the same will be placed on the table of the House.

कोयले की मांग

*266. श्री राम जेठमलानी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में कोयले की मांग का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 में कोयले की कितनी मांग होने का अनुमान है ;

(ग) वर्ष 2001-02 में देश में कोयले के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है;

(घ) क्या यह सच है कि देश में ऐसे बहुत से कोयला भंडार क्षेत्र हैं जिनका दोहन नहीं किया गया है और वहां अभी खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा वहां खनन कार्य आरंभ करने के लिए सरकार की प्रस्तावित योजना क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना को निष्पादित किए जाने के लिए कोयला तथा लिग्नाइट पर गठित कार्यकारी दल ने नौवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2001–02 तक 405.00 मिलियन टन कोयले की मांग होने का अनुमान लगाया है । इस संबंध में मुख्य रूप से क्षेत्र-वार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :—

	(मिलियन टन में) 2001–02
इस्पात	51.60
विद्युत	254.80
अन्य	98.60
जोड़	405.00

(ग) कोयला कंपनियों से कार्यकारी दल द्वारा 2001–02 (नौवीं योजना का अंतिम वर्ष) के लिए अनुमानित कोयले के उत्पादन लक्ष्य का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

	(मिलियन टन में)
कोल इंडिया लि०	303.00
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	36.00
टिस्को/इस्को/डी० वी० सी०	7.60
जोड़	346.60

इसके अलावा कुछ उत्पादन ग्रहीत खनन हेतु उपभोक्ताओं को आवंटित किए गए खनन ब्लाकों से प्राप्त होगा ।

(घ) और (ङ) कुल 44 कोयला क्षेत्रों में से (नार्थ ईस्टर्न क्षेत्र के कोयला क्षेत्रों को छोड़कर, जो कि कुल भंडारों का केवल 0.43% है) केवल 8 ऐसे कोयला क्षेत्र हैं, जिनका कि अभी तक दोहन नहीं किया गया है । इन कोयला क्षेत्रों तथा इनसे संबंधित आगामी कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

राज्य	कोयला क्षेत्र	टिप्पणी
1	2	3
1. पश्चिम बंगाल	1. डोमरा सब-बेसिन	इसमें लगभग 900 मि० ट० के लघु भंडार विद्यमान हैं, जिन्हें अभी प्रमाणित किया जाना है सब-बेसिन का उत्खनन किये जाने का निकट भविष्य में कोई कार्यक्रम नहीं है।
	2. बोरजोरा	इस कोयला क्षेत्र में कठिन भू-गर्भीय परिस्थितियां हैं । वर्तमान में, इन भण्डारों का उत्खनन किया जाना लाभकारी नहीं रहेगा । इन भंडारों का उत्खनन किए जाने के निकट भविष्य में कोई कार्यक्रम नहीं है।

1	2	3
	3. दार्जिलिंग	यह एक बहुत छोटा कोयला क्षेत्र है, जिसके कुल भंडारों की मात्रा 15 मि० ट० की है। वर्तमान में कोई वाणिज्यिक खनन किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।
2. बिहार	4. औरंगा	इस कोयला क्षेत्र का मुख्यत: बिहार सरकार द्वारा दोहन किए जाने का प्रस्ताव है।
3. मध्य प्रदेश	5. गुरुगुडा	यह एक बहुत छोटा कोयला क्षेत्र है, जिसमें लाभकारी रूप से खनन किए जाने की संभावना नहीं है।
	6. तातापानी रामकोला	यह कोयला क्षेत्र अन्वेषण के अधीन है। उक्त क्षेत्र का अन्वेषण पूरा हो जाने पर तथा क्षेत्र की भू-गर्भीय स्थिति को विनिर्दिष्ट कर लिए जाने के बाद सा० ई० को० लि० द्वारा इस कोयला क्षेत्र के दोहन किए जाने पर विचार किया जाएगा।
	7. हासडो-अरुंड	इस कोयला क्षेत्र के दसवीं योजना तथा इसके बाद की अवधि में दोहन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
4. महाराष्ट्र	8. बोखारा	वे० को० लि० द्वारा निकट भविष्य में इस कोयला क्षेत्र का खनन किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

Death of tribal children due to malnutrition in Melghat region of Amravati

*267. SHRI V. RAJESHWAR RAO :

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that 4500 tribal children have died due to malnutrition and for want of food, in the last three years in the Melghat Forest region of Amravati district of Mhaarashtra and if so, what is the information of Government in this regard;

(b) whether Government are also aware more than 250 children have died this year and if proper food supply is not made then more than a thousand children are likely to die in this rainy season;

(c) if so, the steps taken by this department to provide adequate food supply in this area; and

(d) what more will be done by Government here?